



## दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत में कार्बन मूल्य निर्धारण:  
रणनीति और भविष्य की रूपरेखा

[www.nextias.com](http://www.nextias.com)

## भारत में कार्बन मूल्य निर्धारण: रणनीति और भविष्य की रूपरेखा

### संदर्भ

- यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM) के प्रति भारत का दृष्टिकोण, जो वर्तमान में छूट प्राप्त करने पर केंद्रित है, को दीर्घकालिक व्यापार प्रतिस्पर्धा, राजकोषीय स्थिरता और जलवायु नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय कार्बन मूल्य निर्धारण रणनीति में विकसित होना चाहिए।

### यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM)

- इसे व्यापार में कार्बन तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह मूल्य वर्धित कर (VAT) के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है, जो उपभोग के स्थान पर लागू होने वाला गंतव्य-आधारित कर है।
- यह वैश्विक व्यापार को पुनः आकार दे रहा है, कार्बन-गहन वस्तुओं जैसे इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम और उर्वरकों के आयात पर कार्बन कर लगाकर।
- इसका उद्देश्य कार्बन लीकेज को रोकना है, जहाँ कंपनियाँ ढीले जलवायु नियमों वाले देशों में उत्पादन स्थानांतरित करती हैं, और सख्त उत्सर्जन नियमों के अधीन ईयू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।
- जनवरी 2026 से, CBAM यूरोपीय संघ (EU) में जलवायु नीति को सीधे आर्थिक प्रतिस्पर्धा से जोड़ेगा।
- यूनाइटेड किंगडम ने इसी तरह की व्यवस्था अपनाने में रुचि व्यक्त की है और अन्य OECD देशों के भी इसका अनुसरण करने की संभावना है।

### भारत के लिए

- भारत ईयू को इस्पात और एल्युमिनियम का प्रमुख निर्यातक है।
- CBAM निर्यातकों से उनके उत्पादों में निहित उत्सर्जन की रिपोर्ट करने की मांग करता है और 2026 से, ईयू के उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) दर के बराबर कार्बन मूल्य का भुगतान करना होगा।

### कार्बन मूल्य निर्धारण

- यह एक नीतिगत उपकरण है जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, पर वित्तीय लागत लगाता है ताकि प्रदूषण में कमी और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव को प्रोत्साहित किया जा सके।
- यह प्रदूषकों को उनके प्रदूषण से होने वाले पर्यावरणीय हानि के लिए भुगतान करने पर बाध्य करता है, जिससे वे उत्सर्जन कम करने के लिए प्रेरित होते हैं।
- विश्व बैंक की स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट ने वैश्विक जलवायु वित्त और कार्बन मूल्य निर्धारण ढाँचों को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को मान्यता दी है।

### भारत को एक सुदृढ़ कार्बन मूल्य निर्धारण रणनीति क्यों अपनानी चाहिए?

- **CBAM के प्रति संरचनात्मक संवेदनशीलता:** भारत का निर्यात, विशेषकर इस्पात, एल्युमिनियम और सीमेंट, वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक कार्बन-गहन है।
- ये निर्यातकों को भविष्य के कार्बन शुल्कों के प्रति उजागर करते हैं, जबकि अस्थायी CBAM छूट अनुपालन लागत को केवल स्थगित कर सकती है।

- घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण के बिना भारतीय कंपनियाँ दोहरी कराधान (विदेशी CBAM और घरेलू शमन लागत) के जोखिम में हैं।
- **अर्थव्यवस्था का समर्थन:** भारत में केवल लगभग 23% इस्पात निर्यात वर्तमान में CBAM छूट के लिए योग्य हैं।
  - इसे भारतीय निर्यातकों को 'समतुल्य कार्बन लागत समायोजन' का दावा करने में सक्षम बनाकर निष्प्रभावी किया जा सकता है, जिससे ईयू CBAM देनदारियाँ कम होंगी।
  - एक पारदर्शी कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली अनुपालन लागत को घरेलू राजस्व में बदल सकती है, बजाय इसके कि वह ईयू-निर्देशित कर हस्तांतरण बन जाए।
  - OECD ग्रीन फिस्कल रिफॉर्म रिपोर्ट (2024) का अनुमान है कि भारत कार्बन करों या उत्सर्जन व्यापार के माध्यम से GDP का 1.5% तक वार्षिक रूप से एकत्रित कर सकता है, जो हरित अवसंरचना और ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रमों को वित्तपोषित कर सकता है।
- **औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और निम्न-कार्बन नवाचार:** IEA इंडिया एनर्जी आउटलुक 2024 और TERI पॉलिसी पेपर ऑन कार्बन प्राइसिंग (2024) के अनुसार, कार्बन मूल्य निर्धारण ऊर्जा-गहन कंपनियों को कम-उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उत्पादकता में सुधार होता है।
  - दक्षिण कोरिया और चीन से प्राप्त साक्ष्य दिखाते हैं कि कार्बन बाजार पाँच वर्षों में उत्सर्जन तीव्रता को 10–15% तक कम करते हैं।
  - भारत अपने उद्योगों को सीमा शुल्कों से सुरक्षित कर सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा तथा हरित हाइड्रोजन में नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।
- **जलवायु वार्ताओं में भू-राजनीतिक लाभ:** एक घरेलू कार्बन बाजार वैश्विक नेट-जीरो लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत दे सकता है और G20 तथा WTO CBAM चर्चाओं में भारत की वार्ताकारी शक्ति को सुदृढ़ कर सकता है।
- **संस्थागत तैयारी:** भारत के पास पहले से ही परफॉर्म, अचीव, एंड ट्रेड (PAT) योजना और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (RECs) हैं, जो ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्बन बाजार के पूर्ववर्ती हैं।
  - इन्हें एकीकृत कार्बन मूल्य निर्धारण ढाँचे में शामिल करना भारत को 2030 तक वैश्विक बाजारों से जोड़ने की अनुमति देगा।

### भारत की तार्किक प्रतिक्रिया

- **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS):** भारत की प्रस्तावित CCTS (मध्य-2026 में लॉन्च होने वाली) सही दिशा में एक कदम है। हालांकि:
  - कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली, यद्यपि सुरुचिपूर्ण है, संस्थागत रूप से जटिल है।
  - यह सुदृढ़ नियामक क्षमता और परिष्कृत वित्तीय अवसंरचना की मांग करती है, जिनका विकास विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ अभी कर रही हैं।
- **कार्बन कर विकल्प:** कार्बन कर एक सरल, अधिक पारदर्शी और प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य समाधान प्रदान करता है।
  - इसे भारत की वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
  - यह दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाने वाले उद्योगों के लिए मूल्य निश्चितता प्रदान करता है।
  - यह सुनिश्चित करता है कि भारत की राजकोषीय नीति वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन प्रवृत्तियों के अनुरूप हो।

## आगे की राह: भारत में चरणबद्ध कार्बन मूल्य निर्धारण का रोडमैप

- **चरण 1: नींव निर्माण (2025–2027)**
  - कानूनी और संस्थागत ढाँचे की स्थापना।
  - एक केंद्रीय कार्बन मार्केट अथॉरिटी की स्थापना जो डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुपालन की देखरेख करे।
  - मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन (MRV) अवसंरचना का विकास।
  - बड़े औद्योगिक उत्सर्जकों (जैसे विद्युत, इस्पात, सीमेंट, तेल एवं गैस) के लिए उत्सर्जन रिपोर्टिंग को अनिवार्य करना।
- **चरण 2: अनुपालन बाजार की ओर संक्रमण (2027–2030)**
  - बड़े उत्सर्जकों के लिए राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) का शुभारंभ।
  - गैर-आवृत क्षेत्रों (जैसे परिवहन और आवासीय) के लिए कार्बन कर की शुरुआत।
  - अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों (जैसे EU ETS) से जुड़ाव ताकि क्रेडिट ट्रेडिंग संभव हो और CBAM जोखिम कम हो।
- **चरण 3: विस्तार और गहराई (2030–2035)**
  - कृषि, विमानन और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में कवरेज का विस्तार।
  - कार्बन मूल्य को क्रमिक रूप से बढ़ाना।
  - अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना।

## निष्कर्ष: एक रणनीतिक पुनर्संरचना

- कार्बन बोर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक रेजीम परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के लिए सफलता इसमें निहित है:
  - CBAM को एक वैश्विक मानक के रूप में स्वीकार करना, न कि एक लागू किए प्रावधान के रूप में।
  - घरेलू कार्बन कर लागू करना ताकि राजस्व प्राप्त हो सके और निर्यातकों की रक्षा की जा सके।
- सतत व्यापार की नींव के रूप में ईयू के साथ गहन एकीकरण का अनुसरण करना।
- CBAM भारत के लिए राजकोषीय नीति, व्यापार रणनीति और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को संरेखित करने का एक अवसर है, जो इसे खतरे से दूर रखते हुए इसके हरित आर्थिक परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत को दर्शाता है।

Source: BS

## दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न:** भारत में कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र को लागू करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। यह सुनिश्चित करने के लिए किन उपायों को अपनाया जाना चाहिए कि ऐसी नीति उसके विकासात्मक लक्ष्यों और अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हो?

